

दिल्ली
अधिकतम तापमान 41 डिग्री
न्यूनतम तापमान 29 डिग्री

एनसीआर
अधिकतम तापमान 42 डिग्री
न्यूनतम तापमान 29 डिग्री

गुरुवार 22 मई 2025
सूर्योदय प्रातः 05:28 बजे
सूर्यास्त सांय 19:09 बजे

एनसीआर टुडे

करंट न्यूज करंट व्यूज



पृष्ठ 4 भारत का पक्ष रखने की सराहनीय पहल एवं बेतुका विवाद

उत्तर प्रदेश और दिल्ली से एक साथ प्रकाशित **वर्ष : 16 अंक : 216 गाजियाबाद, गुरुवार 22 मई 2025 मूल्य : ₹ 2 पेज : 06 विक्रमी संवत् 2081 युगाब्द 5126 शाक 1946**

केनरा बैंक Canara Bank

SCAN & PAY

UPI ID: 30001262700246@cnrb

BHIM UPI

Digitally signed by CNRB

er DIGITAL SIGNATURE ACCEPTED HERE

ncr MASALA
India's Premium Masala

9410855900 ncrmasala@gmail.com

get online www.ncrmasala.com

गर्म मसाला, हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा व अन्य रसोई मसाले

जोधपुर डीएम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी
* वेबवार्ता. जोधपुर * | जोधपुर डीएम कार्यालय को बुधवार सुबह आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद ऑफिस खाली करा लिया गया। हालांकि, यह धमकी फर्जी निकली। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों को तलाशी के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जोधपुर कलेक्टर कार्यालय की आधिकारिक आईडी पर सुबह करीब 9.30 बजे एक ईमेल प्राप्त हुआ। ईमेल में आरडीएक्स का उपयोग कर दोपहर 3.30 बजे परिसर को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। एक अधिकारी ने बताया कि बीएसएफ, आरपीएफ और सीआईएसएफ की टीमों को भी बुलाया गया और उन्होंने पूरे परिसर की गहन तलाशी ली। उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जोधपुर पुलिस के साइबर विशेषज्ञ ईमेल भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। डीसीपी इंस्ट की साइबर विशेषज्ञों की टीम के साथ-साथ कमिश्नरेंट के साइबर विशेषज्ञ भी जांच का हिस्सा हैं। वे आईपी एड्रेस के साथ यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईमेल किस शहर से भेजा गया था।

IFS के प्रदर्शन मूल्यांकन को लेकर मप्र सरकार का आदेश रह

सुप्रीम कोर्ट ने आईएसएफ अफसर से मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा को अवमानना बताया

* एनसीआर टुडे, नई दिल्ली *
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के उस आदेश को अवमाननापूर्ण करार देकर बुधवार को रद्द कर दिया, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को राज्य में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा का निर्देश दिया गया था।
रिकॉर्ड में यह बात सामने आई है कि मध्य प्रदेश में ऐसे तौर-तरीकों का पालन किया जाता था, जिसमें जिला कलेक्टरों या वरिष्ठ अधिकारियों समेत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएसएफ) अधिकारी भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट दर्ज करते थे।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ उन याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जिनमें प्रथम मुख्य वन संरक्षक के पद तक के अधिकारियों के लिए रिपोर्टिंग प्राधिकारी वन विभाग में उससे ऊपर का वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिए।
श्री शहादत ने कहा था कि केवल प्रधान मुख्य वन संरक्षक के मामले में रिपोर्टिंग प्राधिकारी वन सेवा से संबंधित व्यक्ति के अलावा कोई अन्य होगा, क्योंकि भारतीय वन सेवा में उनसे वरिष्ठ कोई नहीं होता। फिर नियम बनाए सरकार पीठ ने कहा कि मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी राज्य सितंबर शीर्ष अदालत के निर्देशों का इमानदारी से पालन कर रहे हैं। पीठ ने हिदायत दी की वह इस तरह के सरकारी आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकती थी, लेकिन हम ऐसा करने से खुद को रोक रहे हैं और आदेश रद्द कर रहे हैं। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश सरकार शीर्ष अदालत के निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए एक महीने में नियमों को फिर से तैयार करे।



PM बीकानेर में करंगे कई परियोजनाओं का शुभारंभ
* वेबवार्ता. जयपुर *

.....
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को राजस्थान के बीकानेर जिले में रेलवे, सड़क, बिजली, जल और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी 22 मई को राजस्थान के दौर पर जाएंगे।
वे सबसे पहले बीकानेर जाएंगे और बीकानेर-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद, प्रधानमंत्री 26,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
प्रधानमंत्री देश में रेल अवसंरचना को निरंतर बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे।



राज्यों को परेशान करने के लिए राज्यपाल पद का दुरुपयोग: राहुल गांधी

नेता प्रतिपक्ष ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पोस्ट को भी किया रिपोर्ट

* एनसीआर टुडे, नई दिल्ली *
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निर्वाचित राज्य सरकारों की आवाज दबाने और उन्हें परेशान करने के लिए राज्यपाल पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने यह टिप्पणी ऐसे वक्त की है, जब राष्ट्रपति मुर्मु ने पिछले दिनों दुर्लभ स्थितियों में इशतेमाल किए जाने वाले राज्यपाल के अनुच्छेद 143(1) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से सवाल किए हैं। राष्ट्रपति ने शीर्ष अदालत से पूछा है कि क्या राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति के विचार के लिए न्यायिक आदेश के जरिए समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। राहुल गांधी ने 'एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि भारत की ताकत इसकी विविधता में निहित है।
राज्यों का संघ मतलब प्रत्येक की अपनी आवाज है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उन आवाज को दबाने और निर्वाचित राज्य सरकारों को बाधित करने के लिए राज्यपाल पद का दुरुपयोग कर रही है। इसे संघवाद पर एक खतरनाक हमला करार देते हुए विपक्ष के नेता ने कहा कि इसका विरोध किया जाना चाहिए। एक्स पर अपने पोस्ट के साथ उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का एक पोस्ट भी रिपोर्ट किया है, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था।



ईडी ने कर्नाटक के गृह मंत्री से जुड़े संस्थानों पर छापे मारे
* वेबवार्ता. बेंगलुरु * | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों पर बुधवार को छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि तुमकूर में श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज और श्री सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तथा बेंगलुरु के बाहरी इलाके में श्री सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में छापे मारे गए। छापेमारी के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। मुख्यमंत्री का टिप्पणी से इनकार कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थमैया ने ईडी की छापेमारी पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इसकी जांच करूंगा तभी कुछ कहूंगा। वहीं, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों पर छापेमारी की क्या जरूरत है। मेरे गृह मंत्री का किसी मामले में शामिल होना संभव नहीं है। वह एक सभ्य, सरल व्यक्ति हैं। शिवकुमार ने यह भी कहा कि मेरे पास उचित जानकारी नहीं है। इस बारे में मैं जानकारी जुटाता हूँ, फिर कुछ कह पाऊंगा। सुरजवाला ने पिछली भाजपा सरकारों को जिम्मेदार बताया वहीं, कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी और महासचिव रणदीप सिंह सुरजवाला ने परमेश्वर को एक बड़ा एससी नेता बताया।

छत्तीसगढ़ मुठभेड़ में 27 नक्सली ठेर, एक जवान शहीद, कई घायल



* वेबवार्ता. नारायणपुर *
छत्तीसगढ़ के चार विभिन्न जिलों के सुरक्षा बलों के जवानों ने बुधवार को हुई मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए सुरक्षाबलों ने 27 नक्सलियों को ठेर कर दिया और कई अन्य घायल हुये हैं। मुठभेड़ के दौरान एक जवान शहीद हो गया और एक अन्य घायल हो गया है। इस मुठभेड़ में कई बड़े नक्सली लीडर या तो फंसे हुए हैं या फिर मारे गये हैं।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अबुझमाड़ क्षेत्र में सुबह सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। नारायणपुर जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र के माड़ डिवीजन में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) नारायणपुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी बीजापुर और डीआरजी कोंडागांव के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, जिनके पास गृह विभाग का भी प्रभार है, ने बताया कि नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा सीमावर्ती इलाके में बड़ा ऑपरेशन जारी है। सुरक्षाबलों को प्राप्त जानकारी के आधार पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इसमें जवानों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अब तक 27 नक्सली मारे जाने की सूचना मिली है। वहीं इस ऑपरेशन में रूपेश से भी बड़े कमांडर फंसे हुए हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसके साथ ही गृहमंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि मुठभेड़ में एक जवान शहीद और कुछ जवान घायल भी हुए हैं। मारे गए सभी माओवादीयों के शव जवानों के द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। इस मामले की पुष्टि बरतार आईजी सुंदरराज पी. ने की है। श्री सुंदरराज ने प्रेस विज्ञापित के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि बरतार संभाग क्षेत्र में स्थित अबुझमाड़ इलाके में आज सुरक्षाबल के जवानों और माओवादीयों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में जवानों ने 27 माओवादीयों को मार गिराया है। मुठभेड़ के बाद जवानों ने घटनास्थल से मारे गए सभी 27 माओवादीयों के शवों को भी बरामद कर लिया है। इसके साथ ही जवानों ने घटनास्थल से माओवादीयों के कई हथियार भी बरामद किया है। वहीं इस मुठभेड़ में डीआरजी के एक जवान की शहादत के साथ कुछ जवान घायल भी हुए हैं। घायल जवानों को तत्काल मेडिकल हेल्प प्रदान की गई है। घायल जवानों की स्थिति खतरों से बाहर है। बरतार आईजी ने इस घटना में माओवादी संगठन के कई बड़े लीडरों के मारे जाने और घायल होने की भी आशंका जताई है। बताया गया कि अभी भी उक्त इलाके में जवानों के द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है।
मुठभेड़ स्थल पर नक्सलियों के शीर्ष कमांडरों को भी सुरक्षाबलों ने घेर लिया है। इनमें नक्सली लीडर रूपेश और विकल्प के भी फंसे होने की जानकारी सामने आई है। इन दोनों पर सुरक्षा एजेंसियों को लंबे समय से नजर थी और अगर इनकी गिरफ्तारी या मुठभेड़ में मारे जाने की पुष्टि होती है तो यह नक्सल विरोधी अभियान में यह एक बड़ी कामयाबी होगी।

केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील, वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना उचित

* एनसीआर टुडे, नई दिल्ली *
उच्चतम न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दूसरे दिन बुधवार को सुनवाई की और गुरुवार को भी सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष सांलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार के रुख का बचाव किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस्लामी परंपरा संबंधित वक्फ इस्लाम के तहत एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और वक्फ बोर्ड धर्मनिरपेक्ष प्रशासनिक कार्य करते हैं। इसलिए ऐसे बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना संविधान के दायरे में है।
श्री मेहता ने कहा, "वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन वह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दान हिंदू धर्म और ईसाई धर्म सहित हर धर्म में मौजूद है, लेकिन शीर्ष अदालत ने फैसला दिया है कि दान एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। इसी तरह वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन, उचित खाते और ऑडिट सुनिश्चित करना, सभी प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष हैं।"
उन्होंने अग्रे स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड में अधिकतम दो गैर-मुस्लिम सदस्य होने से वक्फ के धार्मिक स्वरूप पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बोर्ड धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।
कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दायर याचिकाओं सहित अन्य में वक्फ कानून के संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह अनुच्छेद 26 के तहत मुस्लिम समुदाय के अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार का उल्लंघन करता है। उनका आरोप है कि संशोधन चुनिंदा रूप से मुस्लिम धार्मिक बंदोबशतों को लक्षित करता है। साथ ही, अनुचित रूप से कठोर पंजीकरण आवश्यकताओं को लागू करता है।



वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को 3 अप्रैल को लोकसभा और 4 अप्रैल को राज्यसभा ने पारित किया और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए।
इन्होंने वक्फ संपत्तियों को पंजीकृत करने के लिए किसी को रोजाना पांच बार नमाज अदा करनी होगी। यह वक्फ की धोखाधड़ी वाली घोषणाओं को रोकने के लिए एक सुरक्षा उपाय है।
उन्होंने कहा, "इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को रोजाना पांच बार नमाज अदा करनी होगी। यह वक्फ की धोखाधड़ी वाली घोषणाओं को रोकने के लिए एक सुरक्षा उपाय है।"
उन्होंने कहा, "इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को रोजाना पांच बार नमाज अदा करनी होगी। यह वक्फ की धोखाधड़ी वाली घोषणाओं को रोकने के लिए एक सुरक्षा उपाय है।"
उन्होंने कहा, "इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को रोजाना पांच बार नमाज अदा करनी होगी। यह वक्फ की धोखाधड़ी वाली घोषणाओं को रोकने के लिए एक सुरक्षा उपाय है।"



यूपी में अब बीएसए पर फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी पाने का आरोप, अपर प्रमुख सचिव से शिकायत

भदोही, एजेंसी। यूपी के अब भदोही जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह पर फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी पाने का आरोप लगा है। यह आरोप गोपीगंज क्षेत्र में जखांव गांव निवासी अशोक कुमार मिश्र ने लगाया है। उन्होंने अपर प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा विभाग) समेत कई अफसरों को पत्र भेजकर मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की। शिकायतकर्ता के मुताबिक भूपेंद्र नारायण सिंह पं. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएड का फर्जी मार्कशीट लगाकर 16 जनवरी, 1991 को शिक्षक बने। श्री भगवंत मान इंटर कॉलेज अहिमित, केराकत (जौनपुर) में उनकी सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति हुई। वह 25 अक्टूबर, 2010 तक वहां कार्यरत रहे। फर्जी मार्कशीट के जरिए उन्होंने 26 अक्टूबर, 2010 को बांदा में सीनियर लेक्चरर की नौकरी हासिल की। वर्ष 1987 में जारी किए गए उनके बीएड मार्कशीट का अनुक्रमंक 18587 है। शिकायतकर्ता का दावा है कि भूपेंद्र नारायण सिंह ने कूटचिंत ढंग से मार्कशीट तैयार की। सच्चाई यह है कि वह 1987 में बीएड में फेल हो गए थे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि भूपेंद्र नारायण सिंह करीब 35 वर्ष से फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी कर रहे हैं। वह इतने साल से वेतन ले रहे हैं। सबसे बड़ा खेल यह है कि उनकी बीएड की मार्कशीट सन् 1985 में गाजीपुर एवं सन् 1987 डोभी (जौनपुर) से है। भदोही बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि औराई ब्लॉक क्षेत्र में बंजारी प्राथमिक विद्यालय में अशोक कुमार मिश्र सहायक अध्यापक थे। उनके खिलाफ शिकायत की गई। जांच में उनकी बीएड मार्कशीट और डिग्री फर्जी मिली। पिछले वर्ष 28 जून को उनकी सेवा समाप्त कर दी गई।

घर से लाखों के गहने और नकदी चोरी

*** एनसीआर टुडे, नोएडा ***
ससुराल गए व्यक्ति के होशियारपुर स्थित घर का ताला तोड़कर चोर लाखों रुपये के गहने और नकदी समेत अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। पड़ोसियों ने वीडियो कॉल कर पीड़ित को घटना की जानकारी दी। सेक्टर-49 पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले को जांच शुरू कर दी है। शिकायत में होशियारपुर गांव के गली नंबर सात में रहने वाले नयन कुमार ने बताया कि 11 मई को वह दोपहर एक बजकर 11 मिनट पर मडर्स डे अक्सर पर अपने ससुराल दिल्ली गए थे। उसी दिन 11 बजे रात को नयन को उसके पड़ोसी ने कॉल की और बताया कि उनके घर का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर रखा सारा सामान बिखरा हुआ है। पूरे घर का वीडियो बनाकर पड़ोसी ने शिकायतकर्ता के मोबाइल पर भेजा। घटना की जानकारी होते ही नयन तुरंत ससुराल से अपने घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर शिकायतकर्ता ने तहकीकात की तो सामने आया कि चोर एक सोने की चेन, एक मंगलसूत्र, सोने की बालियां, सोने का ओम लिखा लॉकेट, सोने की अंगूठी, सोने की नथ, करीब एक लाख रुपये के चांदी के गहने, सिक्के और 25 हजार रुपये की नकदी चुराकर ले गए हैं। इसके बाद शिकायतकर्ता ने डीयन-112 पर कॉल करके पुलिस को घटना की जानकारी दी।

घर के बाहर से जज की कार चोरी

*** एनसीआर टुडे, नोएडा ***
सेक्टर 11 में रहने वाली महिला जज के घर के बाहर से उनकी कार चोरी हो गई। वह दिल्ली के कडकडडूमा कोर्ट में जज हैं। वर्तमान में उनकी तैनाती एनआइ एफ्ट डिजिटल कोर्ट दो में है। मामले की शिकायत सेक्टर-24 थाने में की गई है। महिला के मुताबिक उन्होंने 18 मई की रात अपनी कार घर के बाहर खड़ी की थी। कार पर जज का स्टीकर भी लगा हुआ था। सुबह देखा तो मौके पर कार नहीं थी। सीसीटीवी चेक करने पर पता चला कि चोर रात करीब दो बजकर 50 मिनट पर घर के बाहर आए और कार चोरी कर फरार हो गए। आरोपी की गिरफ्तारी और कार की बरामदगी के लिए एक टीम गठित कर दी गई है।

किशोरी संदिग्ध हालात में लापता

*** एनसीआर टुडे, नोएडा ***
आगहपुर गांव स्थित घर से 15 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों ने सेक्टर-49 थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। किशोरी की सकुशल बरामदगी के लिए एक टीम गठित की गई है। पुलिस को दी शिकायत में महेंद्र मंडल ने बताया कि वह किराये के मकान में परिवार के साथ रहते हैं। 18 मई को शिकायतकर्ता की 15 वर्षीय बेटी घर पर बिना किसी को बताए कहीं चली गई। लोक लाज की वजह से तीन दिन तक शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना किसी को नहीं दी और बेटी को तलाशते रहे। जब बेटी नहीं मिली तो शिकायतकर्ता ने मंगलवार को थाने में घटना की जानकारी दी।

इंजीनियर का घर चोरों ने खंगाला

*** एनसीआर टुडे, नोएडा ***
सेक्टर-71 के ए ब्लॉक स्थित एक घर में किराए पर रहने वाले इंजीनियर के घर में 18 मई को चोरी हो गई। घटना के समय पीड़ित एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित विवेक जाखड़ ने बताया वह पेशे से इंजीनियर हैं। वह एक घर में किराए पर कमरा लेकर रहते हैं। 18 मई की सुबह वह एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। रात में जब घर लौटे तो कमरे का ताला टूटा हुआ था। अंदर घुसकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर पता चला कि चोर उनके घर से लैपटॉप, नकदी, जूते, चप्पल और कपड़ों के अलावा कीमती सामान चोरी कर लिए। पीड़ित की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर चोरों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया। थाना प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पंचमुखी जनता फ्लैट में स्वास्थ्य जांच कैप लगाया गया

*** एनसीआर टुडे, ग्रेटर नोएडा ***
ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित पंचमुखी जनता फ्लैट में बुधवार को बिसरख सीएचसी के द्वारा स्वास्थ्य जांच कैप लगाया गया। कैप में करीब आठ लोगों ने आकर अपनी जांच कराई। इस दौरान दो बच्चों को पीलिया की शिकायत मिली। सेक्टर 3 के डी ब्लॉक स्थित पंचमुखी जनता फ्लैट में करीब 600 परिवार रहते हैं। सोसाइटी में ज्यादातर बच्चों के पीलिया की चपेट में आने के मामले सामने आ रहे। जिसको देखते हुए बिसरख सीएचसी के द्वारा एक कैप लगाया गया। डॉक्टरों ने जाकर सोसाइटी में लोगों की जांच करी।

शादी के नाम पर 25 पुरुषों को ठगने वाली महिला पकड़ी गई

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान पुलिस ने भोपाल से एक 23 साल की महिला को गिरफ्तार किया है। महिला पर आरोप है कि उसने शादी के बहाने लगभग 25 पुरुषों को ठगा था। महिला की पहचान अनुराधा पासवान के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की रहने वाली है। राजस्थान के सर्वाई माधोपुर में विष्णु शर्मा और उनके परिवार को कथित तौर पर धोखा देने के बाद वह कुछ समय से भोपाल में रह रही थी। सर्वाई माधोपुर के मानटाउन पुलिस स्टेशन के अनुसार, विष्णु शर्मा सर्वाई माधोपुर में ठेला चलाते हैं और वह शादी करना चाहते थे। तभी एक पप्पू मोणा नाम का व्यक्ति संपर्क में आया। उसने उन्हें अनुराधा की तस्वीर दिखाई। विष्णु शर्मा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मोणा लड़कियों को मैचमेकिंग के लिए एक स्थानीय पार्क में लाते थे और वहीं उनकी मुलाकात अनुराधा से हुई और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। यह शादी 19 अप्रैल को स्थानीय अदालत में हुई थी। शर्मा ने

आगरा में रेलवे के 122 साल बाद अब मेट्रो ने बनाई टनल

14 किमी में बनेंगे 13 स्टेशन



आगरा, एजेंसी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (यूपीएमआरसी) शहर के बीचों-बीच करीब सात किलोमीटर लंबी मेट्रो टनल बना रही है। आधुनिक तकनीक से लेस टीबीएम मशीन टनल का निर्माण कर रही है। ताजमहल मेट्रो स्टेशन से लेकर आरबीएस कॉलेज तक लगभग टनल तैयार है। इसी सप्ताह में मेट्रो मनकामेश्वर मंदिर पर अप लाइन के कारिडोर में पहला ब्रेक थ्रू लेने की तैयारी में है। लेकिन, ये शहरवासियों के लिए नया नहीं है। 122 साल पहले रेलवे की टनल बनी थी। ब्रिटिशकाल में बेलनगंज व सेंट जॉस के पास 32.3 मीटर लंबी रेलवे टनल बनाई गई थी। बता दें कि यूपीएमआरसी आगरा में 29.4 किलोमीटर

लंबे को कारिडोर का मेट्रो नेटवर्क तैयार कर रहा है। पहला कारिडोर ताजमहल पूर्वी गेट से सिकंदरा के बीच 14 किमी लंबा निर्माणाधीन है, जिसमें 13 स्टेशनों का निर्माण होगा। छह एलिवेटेड और सात भूमिगत स्टेशन होंगे। ताजमहल मेट्रो स्टेशन से लेकर आरबीएस कॉलेज तक करीब सात किलोमीटर की टनल है। आगरा में ये दूसरी रेलवे टनल है। इससे पहले 1903 में ब्रिटिश सरकार ने आगरा सिटी रेलवे स्टेशन और राजा की मंडी रेलवे स्टेशन के बीच में बेलनगंज और सेंट जॉस के पास 32.3 मीटर मीटर लंबी रेलवे सुरंग बनाई गई थी, जिसमें आज भी अप और डाउन में ट्रेन चलती हैं। जानकार बताते हैं कि फ्रेंच और ब्रिटिश इंजीनियरों के

‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ ने बदला ओरछा और पुखरायां स्टेशन का स्वरूप पीएम मोदी 22 मई को करेंगे उद्घाटन

* एनसीआर टुडे, झांसी *

भारत सरकार और रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के प्रथम फेज में चयनित और पुनर्विकसित स्टेशनों का लोकार्पण 22 मई को किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित 103 स्टेशनों का लोकार्पण संपन्न होगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत झांसी रेल मंडल के भी दो स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया है। दरअसल, ओरछा और पुखरायां स्टेशन को विकसित भारत की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। ओरछा रेलवे स्टेशन को 6.5 करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया गया है। इससे यहां के स्थानीय नागरिकों के साथ ही इस नगर में पूरी दुनिया से आने वाले पर्यटकों को आधुनिक सुविधाएं भी मिल सकेंगी। इस स्टेशन को ओरछा मंदिर की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। यहां राजा राम और हनुमान जी की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। यात्रियों की सुविधा और सुगम आवागमन के लिए सर्कुलैटिंग एरिया का विस्तार किया गया है। सर्कुलैटिंग एरिया की बाउंड्री वॉल पर रामायण के दृश्य को दर्शाया गया है। साइकिल और अन्य

गाड़ियों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। इसके अलावा, यहां पर टिकटिंग के लिए आधुनिक और सुविधाजनक टिकट काउंटर बनाए गए हैं और एटीबीएम की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यात्री प्रतीक्षालय को यात्रियों की सुविधा हेतु आधुनिक और आरामदायक बनाया गया है। झांसी मंडल के डीआरएम दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि ओरछा और पुखरायां स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। यात्रियों की सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन के लिए यहां सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। दिव्यांगजनों के लिए शौचालय और रैंप बनाए गए हैं। साथ ही अन्य यात्रियों के लिए पे-एंड-यूज टॉयलेट भी बनाए गए हैं। दोनों ही स्टेशनों में बदलाव दिखाई देगा, जो विकसित भारत की झलक को पेश करता है। बता दें कि पुखरायां रेलवे स्टेशन को 7.22 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। इस पुनर्विकास कार्य के तहत स्टेशन के सर्कुलैटिंग क्षेत्र का विकास और जल निकासी में सुधार किया गया है। साथ ही मौजूदा स्टेशन भवन के अग्रभाग में सुधार के अतिरिक्त एक वीआईपी कक्ष का प्रावधान, प्रतीक्षालय में सुधार, कवर ओवर प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म सरफेसिंग का विस्तार किया गया है।

संभल के प्रमुख चौराहों पर प्रतिमाएं लगाये जाने का प्रस्ताव पारित, विधायक ने की आलोचना

* एनसीआर टुडे, संभल *

संभल नगर पालिका ने शहर के मुख्य चौराहों पर कुछ चुनिंदा हरितियों की प्रतिमाएं लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। समाजवादी पार्टी (सपा) के क्षेत्रीय विधायक इकबाल महमूद ने इसकी आलोचना की है। संभल नगर पालिका के वार्ड संख्या 18 से भारतीय जनता पार्टी की पार्षद चंचल सनी गुप्ता ने बुधवार को बताया कि हाल ही में नगर पालिका की बैठक में उन्होंने शहर के प्रमुख चौराहों पर प्रतिमाएं लगाने का प्रस्ताव रखा था। इनमें चंदौसी चौराहे पर पृथ्वीराज चौहान, शंकर चौराहे पर भगवान परशुराम, सद्गंगापार्क के पास माता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमाएं पहले लगाई जाने की उम्मीद है। हालांकि, संभल सदर सीट से सपा के विधायक इकबाल महमूद ने इस फैसले की आलोचना की है। महमूद ने संवाहदाताओं से कहा कि वह मूर्तियां लगाये जाने के खिलाफ नहीं हैं लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मूर्तियों की स्थापना पर रोक लगायी है अतः चौराहों पर मूर्तियां लगाना अदालत के आदेश की अवहेलना होगा। गुप्ता ने बताया कि बोर्ड ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया है और तीन प्रतिमाओं पर काम शुरू हो चुका है। उनके अनुसार सम्राट



पृथ्वीराज चौहान, भगवान परशुराम और माता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमाएं पहले लगाई जाने की उम्मीद है। हालांकि, संभल सदर सीट से सपा के विधायक इकबाल महमूद ने इस फैसले की आलोचना की है। महमूद ने संवाहदाताओं से कहा कि वह मूर्तियां लगाये जाने के खिलाफ नहीं हैं लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मूर्तियों की स्थापना पर रोक लगायी है अतः चौराहों पर मूर्तियां लगाना अदालत के आदेश की अवहेलना होगा। गुप्ता ने बताया कि बोर्ड ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया है और तीन प्रतिमाओं पर काम शुरू हो चुका है। उनके अनुसार सम्राट

महमूद ने कहा, "मैंने उच्चतम न्यायालय के आदेश की एक प्रति जिलाधिकारी कार्यालय को भेज दी है ताकि उन्हें किसी भी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। मेरी आपत्त मूर्तियों पर नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के संभावित उल्लंघन को लेकर है।" सपा विधायक इकबाल महमूद के विरोध के बारे में पूछे जाने पर पार्षद चंचल सनी गुप्ता ने कहा, "एक बार नगर निगम बोर्ड ने प्रस्ताव पारित कर दिया है तो विधायक उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते।" संभल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मणि भूषण तिवारी ने पुष्टि की कि प्रतिमा स्थापना का प्रस्ताव नगर पालिका बोर्ड ने पारित कर दिया है और इस पर चरणबद्ध तरीके से काम हो रहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेश को लेकर सपा विधायक की चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर तिवारी ने आश्वासन दिया कि प्रतिमा स्थापना का काम 'नियमानुसार' किया जाएगा।

सांसदों को विदेश भेजने को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर उठाए सवाल

नईदिल्ली, एजेंसी। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए सर्वदलीय सांसदों के समूह विदेश जाने की तैयारी में हैं। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों के सांसदों को विदेश भेजने के फैसले के बारे में इसलिए सोचा ताकि वह उन कठिन सवालों का जवाब देने से बच पाएं, जिनके लिए उन्हें वहां बुलाया जा रहा है। बकौल रमेश वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब हो चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धाजलि देते हुए रमेश ने लिखा, 1950 के दशक के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों को हर अक्टूबर-नवंबर में संयुक्त राष्ट्र में भेजा जाता रहा है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में ही इस परंपरा को बंद कर दिया था। लेकिन अब जबकि वह हताश हैं, तो अचानक से उन्हें सभी पार्टियों के सांसदों की याद आई। कांग्रेस नेता ने कहा, पीएम मोदी ने यह फैसला लिया क्योंकि अब वैश्विक और घरेलू स्तर पर पूछे जाने वाले सवालों से

लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की छवि को धक्का लग चुका है। जयराम रमेश ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी का एक वीडियो साझा करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। इस वीडियो में अटल बिहारी बता रहे हैं कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया, जिससे विदेश में उनका इलाज हो सके। वीडियो के केषान में जयराम ने लिखा, मनुष्य के प्रमुख गुण अच्छाई, शालीनता और मानवता होते हैं.. यह गुण नरेंद्र मोदी में उपरिथत नहीं है। इस वीडियो के जरिए हम किसी प्रधानमंत्री के मामिक और सुलझे हुए रूप को समझ सकते हैं, जो कि उनके घूर- विरोधी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद बताया थे। शनिवार को कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार ने उससे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए प्रतिनिधिमंडलों में शामिल करने के लिए चार सांसदों के नाम भेजने के लिए कहा था।



आपके अधूरे सपनों को साकार करना ही मेरा संकल्प है', राजीव गांधी को याद कर राहुल गांधी ने शेर्य का भावुक पोस्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्हें याद किया है। राहुल गांधी ने अपने पिता के नाम एक भावुक पोस्ट भी शेयर किया। उन्होंने लिखा कि पापा, आपके यादें हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करती हैं। राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर दो तस्वीरों को शेयर किया। एक तस्वीर में वह अपने पिता के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर राजीव गांधी की समाधि स्थल की है, जहां राहुल अपने पिता को हाथ जोड़कर श्रद्धाजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने इन तस्वीरों के साथ एक भावुक संदेश भी साझा किया। उन्होंने लिखा, पापा, आपके यादें हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करती हैं। आपके अधूरे सपनों को साकार करना ही मेरा संकल्प है और मैं इन्हें पूरा करके रहूंगा। इससे पहले कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें साझा की थीं। उन्होंने लिखा, स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वीर भूमि पर उन्हें श्रद्धाजलि अर्पित की। राजीव गांधी के दूरदर्शी नेतृत्व ने हमारे राष्ट्र की नींव को बदल दिया, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित है। उनकी स्थायी विरासत हमारे दुष्टकोण का मार्गदर्शन करती रहती है। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धाजलि दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करता हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी राजीव गांधी को याद किया।

इसलिए हमें धोखा देने में उसे 13 दिन लग गए। 2 मई को, अनुराधा ने कथित तौर पर अपने ससुराल वालों को दिए गए खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। शर्मा ने कहा कि हमने छेले-भट्टरे बनाए थे लेकिन मुझे शक है कि उसने पानी में कुछ मिलाया था। उस रात भी मैंने उससे पूछा था कि मेरी आंखें इतनी भारी क्यों लगी रहीं। उन्होंने आगे कहा कि वह थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही थी। हालांकि, वह सो गए। पुलिस ने बताया कि जब वे अगली सुबह जागे, तो उन्हें पता चला कि वह गहने, नकदी और एक मोबाइल फोन लेकर घर से भाग गई थी। सहायक उप-निरीक्षक मीठा लाल यादव ने बताया कि 3 मई को विभिन्न धाराओं के तहत एफएआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें धोखाधड़ी से संबंधित धाराएं भी शामिल हैं। उप-निरीक्षक मीठा लाल यादव ने बताया कि हमने मैरिज एग्रीमेंट देखा, जिसमें उसका पता लिखा था और भोपाल में उस जगह पहुंचे। हमें पता चला कि उसके द्वारा दिया गया पता झूठा था।



बताया कि उन्होंने मीणा को 2 लाख रुपये नकद दिए थे, जिसमें उधार लिए गए पैसे भी शामिल थे। पप्पू मीणा ने ही यह रिश्ता तय करवाया था। शादी के बाद वह और अनुराधा पति-पत्नी के रूप में साथ रहने लगे। विष्णु शर्मा ने बताया, उनकी कार्यप्रणाली के अनुसार, गिराह के सदस्य शादी के 5-7 दिनों के भीतर आधी रात को अनुराधा को उठ ले जाते थे। विष्णु शर्मा ने आगे कहा कि हालांकि, मेरा फास्ट-फूड का ठेला है और इसलिए मैं रात 10.30 बजे तक ही लौट पाता था, फिर खाना खाता था और आधी रात के बाद तक टेलीविजन देखता था। इस दौरान कोई न कोई देर रात तक जागता रहता था,

आंधी में उड़ गया ‘विकास’

दिल्ली-एनसीआर को गत दिनों तेज आंधी, बारिश व तूफान का सामना करना पड़ा। इस तेज आंधी में नई दिल्ली स्टेशन के क़रीब नबी करीम क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई जिसमें दब जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गये। जबकि कई जगहों पर पेड़ उखड़ने का भी समाचार है। परन्तु शायद इस आंधी का सबसे अधिक प्रकोप न्यू अशोक नगर रैपिड मेट्रो स्टेशन को झेलना पड़ा। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम के बीच आने वाले इस स्टेशन के एक बड़े हिस्से की छत ही तेज हवा के चलते उड़ लगी। और छत की कई टीन नीचे सड़क पर जा गिरी तो कई हवा में लटकने लगीं।

गौरतलब है कि अभी क़रीब चार माह पूर्व ही 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली-मेरठ रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम के 13 किलोमीटर लंबे जिस सेक्शन का उद्घाटन किया था, न्यू अशोक नगर स्टेशन भी उसी सेक्शन के बीच आने वाला एक प्रमुख स्टेशन है। और यह नवनिर्मित स्टेशन आंधी-तूफ़ान का एक झटका भी नहीं झेल पाया। दिल्ली के न्यू अशोक नगर को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से जोड़ने वाली इस परियोजना में 4, 600 करोड़ रुपये की लागत आई है। न्यू अशोक नगर रैपिड मेट्रो स्टेशन पर हुये इस हादसे के बाद सुरक्षा के दृष्टिगत नमो भारत ट्रेन की सेवाओं के आवागमन को अगले आदेश तक स्थगित करना पड़ा था। इस हादसे के बाद एक बार फिर स्टेशन की छत के निर्माण की गुणवत्ता पर प्रश्न उठने लगे हैं।

यहाँ एक बात यह भी क़ाबिले गौर है न केवल प्रधानमंत्री नई ट्रेन को झंडी दिखा कर ख़ाना करते हैं बल्कि पुल, हाईवे एक्सेसवे के छोटे से नवनिर्मित हिस्से जैसी परियोजनाओं का भी वे स्वयं उद्घाटन करते हैं बल्कि ऐसे अवसरों पर प्रायः कांग्रेस की सरकार को कोसने और अपनी पीठ थपथपाने से भी नहीं चूकते। मिसाल के तौर पर गत वर्ष द्वाका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री ने तंज करते हुये कहा था कि “कांग्रेस ने 7 दशक तक जो गूठे खोदे थे वे अब तेजी से भर जा रहे हैं।

उसी समय उन्होंने यह भी कहा था कि ‘मैं न छोटा सोच सकता हूं, न मैं मामूली सपने दे सकता हूँ और न ही मैं मामूली संकल्प करता हूं। मुझे जो चाहिए विराट चाहिए। विशाल चाहिए और तेज गति से चाहिए क्योंकि 2047 में मुझे देश को ‘विकसित भारत’ के रूप में देखना है।’ परन्तु उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे हर परियोजना का निर्माण टिकाऊ व मजबूत भी चाहिए। यह कौजिन 16 जुलाई को प्रधानमंत्री ने जलिया जालौन के कैथेरी में पूरे प्रचार-प्रसार के साथ जिस बुदेलखंड एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया था वह एक्सप्रेस-वे उद्घाटन के केवल 5 दिन बाद ही जगह-जगह से धंस गया था और उसमें कई जगह बड़े बड़े गूठे पड़ गये थे। जिसके कारण कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गये थे। चित्रकूट के भरतकूप से शुरू होकर इटावा के कुदरेल में मिलने वाले इस बुदेलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण पर क़रीब 14 हजार करोड़ की लागत आई थी। इसके एक वर्ष बाद फिर इसी एक्सप्रेस वे पर पुनः चित्रकूट को जाने वाली लेन पर क़रीब एक दर्जन गूठे हो गए थे। इन गूठों में पानी भरने से एक्सप्रेस वे से निकलने वाले कई वाहनों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ा था। उस समय भी मीडिया में इस परियोजना की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किये गए थे और काफ़ी घंटिया निर्माण के चलते सरकार की काफ़ी फ़ज़ीहत हुई थी। जाहिर है यह गूठे कांग्रेस के समय के नहीं थे।

इसी तरह देश के सबसे लंबे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर दौसा ज़िले के भांडारेज के पास पर भारी वाहन गुजरने से सड़क धंस गई, जिससे बड़ा ग़ाड़ा हो गया था। इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया था। यहाँ भांडारेज टोल के पास भारी वाहन गुजरने मात्र से सड़क धंस गई थी जिससे सड़क के बीचों-बीच 15 फ़ुट गहरा ग़ाड़ा हो गया था। इस एक्सप्रेस वे पर गूठे होने के बाद इसमें भी घंटिया निर्माण सामग्री के इश्तेमाल तथा लापरवाही का आरोप लगा था। इस परियोजना के निर्माण पर भी लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की लागत आई थी। 12 फ़रवरी 2023 को इस का भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही उद्घाटन किया था और उद्घाटन करते हुये इसे भी देश की आधारभूत संरचना का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया था।

लेकिन उद्घाटन के कुछ ही महीनों में बारिश ने इस ‘उत्कृष्ट निर्माण’ की वाश्तकियात को उजागर कर दिया था। इस तरह के दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जो या तो निर्माण के समय ही ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गये या उद्घाटन के कुछ समय बाद ही उनकी अस्तित्वात उजागर हो गईं। अभी गत वर्ष बिहार में इस्तरह एक के बाद एक कई बड़े पुल ढह गए। गत वर्ष अयोध्या नगरी में कई जगह सड़कें धंस गयीं। चंडीगढ़ से राजस्था को जाने वाला अंबाला से होकर गुजरने वाला हाहवे अपने निर्माण के कुछ ही समय बाद क्षतिग्रस्त हो गया था। इसपर बने कई पुल भारी वहां गुजरने पर आज भी थरथर हिलते हैं। यह सारे ‘गूठे’ विकसित राष्ट्र के मार्ग में पड़ने वाले गूठे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी न ही कांग्रेस की है न ही पंडित नेहरू की।

सवाल यह है कि इस तरह के घंटिया निर्माण के पीछे का रहस्य आख़रि क्या है? कौन हैं इन कंपनीज के मालिक जो जनता के टैक्स के पैसों की इस्तरह खुलकर लूट करते हैं? जनधन की लूट खसोते का यह सिलसिला शाहिरि कभी ख़त्म भी होगा या नहीं? इन लूटेरी निर्माण कंपनियों को किसकी आश मिली हुई है? क्या वजह है कि जिन मुग़लों को विशिेश व आक्रान्त बताकर दिन रात वोट बटोरने की राजनीति की जाती है उनके समय के बनाये हुये हजारों निर्माण आज भी पूरी मजबूती के साथ अपना सिर बुलंद किया खड़े हैं। इसी तरह अंग्रेज़ों के शासनकाल के अनेक महत्वपूर्ण निर्माण आजतक क्षतिग्रस्त नहीं हुये। उदाहरणार्थ 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर-जनरल लॉर्ड इचिन द्वारा उद्घाटित व ब्रिटिश वास्तुकारों एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किये गये पुराने संसद भवन का आज तक बाल भी बँका नहीं हुआ जबकि सेन्ट्रल विक्टा परियोजना के अंगंतत बना नया संसद भवन जिसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था उसमें पहली बारिश के दौरान ही पानी टपकने लगा था। निश्चित रूप से यह इस भवन की गुणवत्ता या निर्माण में कमी के कारण ही था। इससे नये संसद भवन की प्रस्ताह को भी ठेस पहुँची थी। परन्तु आश्चर्य है कि भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरंस व विकास का हर वक्रतू हिंदीरा पीटने वाली सरकार का ‘विकास’ कहीं गूठों में घुसा जा रहा है तो कहीं आंधी में उड़ा जा रहा है?

सुरक्षा में संघ : खुफिया एजेंसियों की नाकामी

हरियाणा के कई जिलों में संदिग्ध व्यक्तियों ने पाकिस्तान जाकर महीनों बिताए, सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कीं, फिर भी भारतीय खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। ज्योति और तारिफ जैसे लोग फर्जी पहचान से पासपोर्ट बनवाकर सीमा पार पहुंचे, पाकिस्तानी अधिकारियों से मिले, और बेधड़क लौट आए। यह मामला न सिर्फ इंटीलजेंस विफलता को उजागर करता है, बल्कि हमारे साइबर निगरानी तंत्र और पासपोर्ट वेरिफिकेशन की कमजोरी को भी सामने लाता है। जब सोशल मीडिया पर जासूसी खुलेआम हो रही हो, तब खामोश एजेंसियाँ देश की सुरक्षा को संकट में डाल रही हैं... प्रियंका सौरभ

आज जब भारत चंद्रयान-3 की सफलताओं, डिजिटल इंडिया की उड़ानों और वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ खड़ा है, तब एक छोटी सी खबर राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव हिला देने वाली बन जाती है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा के अलग-अलग जिलों में संदिग्ध जासूसी गतिविधियाँ होती रहीं, संदिग्ध व्यक्ति पाकिस्तान भी गए, महीनों तक वहां रहे, सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कीं—पर खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। अगर यह खतरनाक लापरवाही नहीं तो और क्या है? **जासूसी की कहानी या एजेंसियों की नींद?** चंडीगढ़, अंबाला, हरिसा, यमुनानगर और पंचकुला जैसे संवेदनशील जिलों में संदिग्ध लोगों की गतिविधियाँ चलती रहीं। ज्योति और तारिफ जैसे व्यक्तियों के पास तीन-तीन नाम थे, वे पाकिस्तान गए, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालते रहे, वहां के अधिकारियों से मिले, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नींद नहीं टूटी। यह सिर्फ एक केस नहीं, यह उन सिस्टम पर सवाल है जो कागज़ों में तो मजबूत दिखता है लेकिन जमीनी हकीकत में खामोश रहता है। क्या यह माना जाए कि आज सोशल मीडिया के दौर में भी हमारी एजेंसियाँ उन गतिविधियों को पकड़ नहीं पाती जो खुल्लमखुल्ला हो

गाजियाबाद, गुरुवार 22 मई 2025

भारत का पक्ष रखने की सराहनीय पहल एवं बेतुका विवाद

ललित गर्ग

पहलगाम की क्रूर एवं बर्बर आतंकी घटना एवं उसके बाद भारत के सिंदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान को करारी मात देने की घटना से निश्चित ही भारत की ताकत को दुनिया ने देखा। लेकिन इसके बाद पाक दुनिया से सहानुभूति बटोरने के लिये जहां विश्व समुदाय में अनेक भ्रम, भ्रांतिया एवं भारत की छवि को छिछालेदार करने में जुटा है, वहीं भारत का उर दिखा-दिखा कर ही पाक अनेक देशों से आर्थिक मदद मांग रहा है।

इन्हीं स्थितियों को देखते हुए दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने के लिए केंद्र सरकार ने जिस तरह से सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों का गठन किया है, यह फैसला जितना सराहनीय है, उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण एवं विडम्बनापूर्ण है इसका राजनीतिक विवादों में घिर जाना। यह राजनीति से ऊपर, मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रतिबिंब बनना चाहिए। देश की सुरक्षा, सैन्य उपक्रम, राष्ट्रीय एकता-अखण्डता एवं विदेश नीति से जुड़े विषय पर राजनीति होना, देश के हित में नहीं है।

पहलगाम हमले के बाद यह अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का बचाव करने या उसके साथ मुखरता से खड़े होने वाले देशों या विश्व संगठनों के साथ-साथ भारतीय राजनीतिक दलों में विवाद का बढ़ना चिन्ताजनक है।

भारत के राजनीतिक दल प्रारंभ में एकजुट दिखे लेकिन राजनीतिक स्वार्थों के चलते अब उनमें कहीं-कहीं वैचारिक मतभेद उभर रहे हैं। पाकिस्तान दोषी होने के बावजूद पीड़ित होने का स्वांग रचकर सहानुभूति जुटाता रहा है। दुनिया के अनेक देश उसके झंसे में आ भी जाते हैं। ऐसे में, दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में भारत का पक्ष रखने का मोदी सरकार का यह प्रयास बहुत जरूरी एवं दूरगामी सोच से जुड़स है। इस प्रयास को एक बड़े अभियान के रूप में लेना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ भारत की श्रेय सहिष्णुता और ऑपरेशन सिंदूर का संदेश दुनिया तक पहुंचना चाहिए।

अप्रेशन सिंदूर के दौरान सभी दलों ने सरकार

और सेना के प्रति समर्थन जताया था। सरकार ने भी उसी भावना का सम्मान करते हुए सभी दलों के सांसदों को प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया है। कांग्रेस ने थरूर का नाम नहीं भेजा था, सरकार ने उन्हें अपनी तरफ से शामिल कर लिया। जिनके नाम कांग्रेस ने दिए थे, उनमें से सिर्फ आनंद शर्मा चुने गए।

शशि थरूर विदेश नीति के जानकार है। थरूर पहले संयुक्त राष्ट्रसंघ में काम कर चुके हैं, विदेश राज्यमंत्री रह चुके हैं। उनके अनुभव का फायदा निश्चित रूप से प्रतिनिधिमण्डल को मिलेगा, दुनिया में भारत का पक्ष सही परिप्रेष्य में रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हालांकि कांग्रेस को लगता है कि उसके सांसद को चुनने से पहले उसी खसई पूछा जाना चाहिए था, इस अपेक्षा को गलत भी नहीं कहा जा सकता।

मगर वर्तमान संवेदनशील हालातों में इसे विवाद का मुद्दा बनाने से बचा जा सकता था। लेकिन कांग्रेस के सदस्यों, खासकर सांसद शशि थरूर को लेकर हो रहा विवाद बिल्कुल अनचाहा एवं अनुचित है।

इससे एक अच्छा एवं प्रासंगिक मकसद नकारात्मक खबरों में घिर गया है। भले ही शशि थरूर और कांग्रेस के रिश्ते पिछले कुछ समय से ठीक नहीं रहे हैं। लेकिन यह एक सांसद और उसकी पार्टी के बीच का मसला है। यहां जो मुद्दा सामने है, वह देश से जुड़ा है। इसमें सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए।

युद्ध एवं आतंक जैसे हालातों में भारत ने अपना पक्ष रखने के लिए पहले भी समय-समय पर विश्व के शीर्ष नेताओं को आगे किया है और उसी परिपटी को मोदी सरकार ने आगे बढ़ाकर देश की राजनीति व राजनय को मजबूती दी है। सात सदस्यीय बैजयंत जय शंका, रविशंकर प्रसाद, शशि थरूर, संजय झा, श्रीकांत शिंदे, कनिमोझी करुणानिधि और सुप्रिया सुले के नेतृत्व में हमारे देश के नेता 32 देशों का दौरा करेंगे।

यह विपक्ष के नेताओं के लिए भी स्वर्णिम अवसर है कि वह अपनी काबिलियत एवं देशहित को देश के सामने साबित करें। क्योंकि राष्ट्र एवं राष्ट्रीय एकता सबसे ऊपर है। बांटने

संपादकीय



वाली राजनीति से अलग जग हम देशहित के पक्ष में खड़े होंगे, तभी आतंकवाद से लड़ने में सहूलियत एवं सफलता मिलेगी।

क्या दुनिया ने भारत के सीमित सैन्य अभियान के महत्व, संयम और समझदारी को ठीक से समझा है? क्या भारत आतंकवाद के खिलाफ संपूर्ण युद्ध नहीं छेड़ सकता था? अगर भारत ने युद्ध को नहीं बढ़ाया, तो इसका अर्थ काई यह नहीं कि भारत का पक्ष कमजोर है। भारत चाहता तो पाक को हर मोर्चे पर नेशतनाबूद कर सकता है, लेकिन भारत का लक्ष्य आतंकवाद को समाप्त करना है।

भारत ने पाकिस्तान और पीओके में बसे 9 आतंकी ठिकानों को रात के अंधेरे में तबाह कर दिया। इसके बाद भारत ने ठान लिया कि पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद परशत पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करना है, जिसकी जिम्मेदारी अनुभवी एवं विशेषज्ञ सात सांसदों को सौंप कर सरकार ने सूझबूझ एवं परिपक्व नेतृत्व का परिचय दिया है। सांसदों के सात प्रतिनिधिमंडल दुनियाभर के देशों में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखेंगे।

हर एक प्रतिनिधिमंडल में 6-7 सांसद और कई राजनयिक शामिल होंगे। भारत की शांति,



अहिंसा, विकास एवं विष्व बंधुत्व का संदेश सात प्रतिनिधिमंडलों के जरिये दुनिया तक पहुंचना इसलिए भी जरूरी है कि भारत को तेज विकास करना है और अब वह पहलगाम जैसे किसी आतंकी हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। गौर करने की बात है कि सात प्रतिनिधिमंडलों में 59 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिनमें सतारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के 31 नेता और अन्य दलों के 20 नेता शामिल हैं।

इस तरह सर्वदलीय सांसदों की टीमों को अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक मिशन पर भेजने से भारत का पक्ष मजबूत होगा, दुनिया में आतंक के विरुद्ध सकारात्मक वातावरण बनेगा। ये दौर न सिर्फ आतंकवाद पर भारत की नीतियों को साफ करेगे, बल्कि पाक की हरकतों को भी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे।

सात प्रतिनिधिमंडलों में जिन नेताओं को नेतृत्व दिया गया है, उसमें भी अन्य दलों को प्रार्थमिकता देकर एक संयुक्त एवं सूझबूझ का परिचय दिया गया है। आईडिया ऑफ़ इंडिया के साथ सुगठित इस टीम इंडिया के कंधे पर बड़ी एवं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। दुनिया के निर्णायक नेताओं से मिलकर यह बताना जरूरी है कि

(लेखक पत्रकार एवं संतंभकार है)

जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का संकट

योगेश कुमार गोयल

मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी पर जैव विविधता पर गंभीर संकट मंडरा रहा है और जीव-जंतुओं, वनस्पतियों इत्यादि की अनेक प्रजातियां तेजी से लुप्त होती जा रही हैं। जीव-जंतु और वनस्पति ही धरती पर बेहतर और जरूरी पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करते हैं लेकिन प्रदूषित वातावरण और प्रकृति के बदलते मिजाज के कारण जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है।

अनेक शोधों से यह चिंताजनक तथ्य सामने आ चुका है कि पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र बेहद खराब हो चुका है। मानवीय दखल से दूर रहने के कारण और स्थानीय जनजातीय लोगों की भूमिका के चलते धरती का केवल तीन प्रतिशत हिस्सा ही पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित रह गया है। जैव विविधता के मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता और समझ बढ़ाने तथा धरती पर मौजूद जंतुओं और पौधों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष 22 मई को एक खास थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का इस वर्ष का विषय है ‘प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास’, जो न केवल पर्यावरण संरक्षण की वैश्विक प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है बल्कि जैव विविधता और सतत विकास के बीच गहरे अंतर्संबंध को भी उजागर करता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी आफ एरिजोना के शोधकर्ताओं का मानना है कि अगले पांच दशकों में जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की प्रत्येक तीन में से एक यानी एक तिहाई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी।

शोधकर्ताओं ने दुनियाभर के छह सौ स्थानों



पर पांच सौ से ज्यादा प्रजातियों पर एक दशक तक अध्ययन करने के बाद पाया कि अधिकांश स्थानों पर 44 प्रतिशत प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इस अध्ययन में विभिन्न मौसमी

कारकों का अध्ययन करने के बाद शोधकर्ताओं इस नतीजे पर पहुंचे कि यदि गर्मी ऐसे ही बढ़ती रही तो 2070 तक दुनियाभर में कई प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। ब्रिटेन स्थित ‘स्मिथसोनियन एनवायरनमेंटल रिसर्च सेंटर’ के मुताबिक विश्व के केवल 2.7 प्रतिशत हिस्से में ही अप्रभावित जैव विविधता बची है, जो बिल्कुल वैसी ही है, जैसी पांच सौ वर्ष पूर्व हुआ करती थी। इन क्षेत्रों में सदियों पहले जो पेड़-पौधे और जीव पाए जाते थे, वे प्रजातियां आज भी मौजूद हैं। जो अप्रभावित जैव विविधता वाला क्षेत्र बचा है, वह भी जिन-जिन देशों की सीमाओं के अंतर्गत आता है, उनमें से केवल 11 प्रतिशत क्षेत्र को ही संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। अप्रभावित जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से

अधिकांश इलाके उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, जहां मानव उपस्थिति कम रही है, लेकिन अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ये जैव विविधता से समृद्ध नहीं थे।

‘इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर’ (आइयूसीएन) एक रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में वन्यजीवों और वनस्पतियों की हजारों प्रजातियां संकट में हैं और आने वाले समय में इनके विलुप्त होने की संख्या तथा दर में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। आइयूसीएन ने करीब एक लाख पतैस हज़ार प्रजातियों का आकलन करने के बाद इनमें से सैंतीस हज़ार पर सात सौ प्रजातियों को विलुप्ति के कगार पर मानते हुए खतरे की सूची में शामिल किया था। आइयूसीएन के अनुसार नौ सौ से ज्यादा जैव प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और 37 हज़ार से ज्यादा प्रजातियां पर विलुप्त होने का संकट मंडरा रहा है। वल्ड वॉइड लाइफ क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक वन्यजीवों की तस्करी भी दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरी है। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक

तस्करी रतनधारी जीवों की होती है। वन्यजीव तस्करी में 22 प्रतिशत तस्करी के मामले रेंगने वाले जीवों के और 10 प्रतिशत पक्षियों के होते हैं जबकि पेड़-पौधों की तस्करी का हिस्सा 14.3 फीसद है।

‘स्टेट ऑफ वॉर्ल्ड बर्ड्स’ नामक एक रिपोर्ट में यह तथ्य भी सामने आ चुका है कि दुनिया में पक्षियों की करीब 39 प्रतिशत प्रजातियां की संख्या स्थायी है और मात्र 6 प्रतिशत प्रजातियां ही ऐसी हैं, जिनकी संख्या बढ़ रही है, जबकि 48 प्रतिशत प्रजातियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। पक्षियों की प्रजातियों की संख्या में गिरावट को भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में जहां 14 प्रतिशत प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं केवल 6 प्रतिशत प्रजातियां की संख्या ही स्थिर है जबकि 80 प्रतिशत प्रजातियां कम हुई हैं। इनमें से 50 प्रतिशत प्रजातियों की संख्या में भारी गिरावट और 30 प्रतिशत प्रजातियों में कम गिरावट दर्ज की गई है।

सालाना पक्षी गणना में अब प्रतिवर्ष पक्षियों की संख्या और विविधता में गिरावट आ रही है, जिसका बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन और जंगलों का कटना है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पक्षियों पर हुए शोध के नतीजे भी चौंकाते हैं। वहां वन क्षेत्रों में मानवीय दखल, वनों की कटाई और तेजी से बढ़ते प्रदूषण के कारण पक्षियों की संख्या में 60-80 प्रतिशत तक की कमी आई है।

पर्यावरण वैज्ञानिकों के मुताबिक जैव विविधता के क्षरण का सीधा असर भविष्य में कृषि, खाद्य पैदावार इत्यादि पर पड़ेगा। इसलिए पृथ्वी पर जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि हम पर्यावरणीय संतुलन को न बिगड़ने दें। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस प्रकार जंगलों में अतिक्रमण, कटाई, बढ़ता प्रदूषण

और पर्यटन के नाम पर गैर जरूरी गतिविधियों के कारण पूरी दुनिया में जैव विविधता पर संकट मंडरा रहा है, वह पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का स्पष्ट संकेत है और यदि इसमें सुधार के लिए शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में बड़े नुकसान के तौर पर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।

विकास के नाम पर किए गए विनाशकारी कटाई बदर्शूर जारी रही और जीव-जंतुओं तथा पक्षियों से उनके आवास छीने जाते रहे तो ये प्रजातियां धरती से एक-एक कर लुप्त होती जाएंगी और भविष्य में इससे पैदा होने वाली भयावह समस्याओं और खतरों का सामना समस्त मानव जाति को ही करना होगा।

बहरहाल, शोधकर्ताओं का पृथ्वी पर जैव विविधता के अस्तित्व पर मंडराने संकट को लेकर कहना है कि अधिकांश प्रजातियां मानव शिकार के कारण लुप्त हुई हैं जबकि कुछ अन्य कारणों में दूसरे जानवरों का हमला और बीमारियां शामिल हैं।

हालांकि उपग्रहों से मिली तस्वीरों के आधार पर शोधकर्ताओं का मानना है कि धरती के ऐसे बीस फीसद हिस्से की जैव विविधता को बचाया जा सकता है, जहां अभी पांच या उससे कम बड़े जानवर ही गायब हुए हैं लेकिन इसके लिए मानव प्रभाव से अछूते क्षेत्रों में कुछ प्रजातियों की बसावट बढ़ानी होगी ताकि पारिस्थितिकीय तंत्र में अस्तुतुलन पैदा न हो।

जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही गर्मी से भी जैव विविधता खतरे में पड़ी है। जैव विविधता पर संकट यदि इसी प्रकार मंडराना रहा तो धरती से प्राणी जनत का खस्ता होने में सैकड़ों साल नहीं लगाने वाले।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, पर्यावरण मामलों के जानकार और ‘प्रदूषण मुक्त संस’ पुरतक के लेखक हैं)

जएं।
2. आंतरिक निगरानी तंत्र का विकेंद्रीकरण – हर जिले में स्थानीय इंटीलजेंस टीम हो जो संदिग्धों की पहचान से अछूते रहें।
3. फर्जी पहचान की जांच के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री – आधार, पैन, पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों की एकीकृत जांच प्रणाली विकसित की जाए।
4. राजनीतिक जवाबदेही तय हो – अगर सुरक्षा काकू होती है, तो जवाबदेह अफसरों पर कार्यवाही हो।
5. मीडिया की भूमिका – राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मीडिया को निष्पक्ष, सक्रिय और खोजी रख अपनाना चाहिए।
कम जागो सिस्टम?
‘जासूसी होती रही, एजेंसियां सोती रहीं’—यह वाक्य केवल एक खबर नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की नींव पर तमाचा है। यह हमें याद दिलाता है कि कितनी भी तकनीक आ जाए, जब तक इरादा और निगरानी नहीं होगी, तब तक देश की सुरक्षा कागज़ों तक ही सीमित रहेगी। हमें न केवल खुफिया एजेंसियों की जवाबदेही तय करनी होगी, बल्कि नागरिकों को भी जागरूक बनाना होगा कि आज की दुनिया में सुरक्षा केवल फौजों से नहीं, बल्कि संसक नागरिकों से भी सुनिश्चित होती है। जागिए, क्योंकि जासूस सोते नहीं।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती आशा शर्मा द्वारा 707 मंदाकिनी टावर सेक्टर -4, वैशाली गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) भारत से प्रकाशित एवं एन.सी.आर. प्रिंटर्स, 15/19 साइट-4, साहिबाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया जनपद गाजियाबाद से मुद्रित।
संपादक : संजय शर्मा
फ़ोन : 9899683800
वेबसाइट : www.ncrtoday.in

ई-मेल: todayncr@gmail.com >>> ncrtoday@hotmail.com

RNI-UPHIN/2009/30721

